

LM-102/1002**The Indian Constitutional Law : The New Challenge**

(भारतीय संवैधानिक विधि : नवीन चुनौतियाँ)

Master or Law (LLM-11/12/16)

First Year, Examination, 2017

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. When can the President's rule be imposed under Article, 356 of the constitution ? To what extent the Supreme Court has put a check on motivated and arbitrary dismissal of State Government by the Centre under Article 356 ? Refer to decided cases.

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है ? किस सीमा तक उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र द्वारा अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, अभिप्रेरित और मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त करने पर रोक लगा दी है ? निर्णीत वादों का सन्दर्भ दीजिए।

2. Discuss the meaning and scope of fundamental right to 'Equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.' Also discuss the basis and test to reasonable classification under Article 14.

भारतीय भू-भाग में 'विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण' के मौलिक अधिकार के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत युक्तियुक्त वर्गीकरण के आधार एवं कसौटी की भी विवेचना कीजिए।

3. What is Judicial Activism ? In this context, evaluate the contribution of the Supreme Court of India, which is empowered to act as the guardian of the constitutional provisions. Refer to decided cases.

न्यायिक सक्रियतावाद क्या है ? इस सम्बन्ध में भारतीय उच्चतम न्यायालय के, जिसे सांविधानिक प्रावधानों के रक्षक का अधिकार दिया गया है, योगदान का मूल्यांकन कीजिए। निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए।

4. Critically examine the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy in the light of constitutional amendments and decided cases.

मूल अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के मध्य सम्बन्धों का, सांविधानिक संशोधनों एवं निर्णीत वादों के प्रकाश में, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What is the procedure for formation of a new State ? Explain.

एक नये राज्य के सृजन की प्रक्रिया क्या है ? स्पष्ट कीजिए।

2. Write an essay on 'doctrine of separation of powers.'
'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त' पर एक लेख लिखिए।
3. Discuss the 'procedure of impeachment' of a judge of Supreme Court.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध 'महाभियोग की प्रक्रिया' का वर्णन कीजिए।
4. Explain the meaning and scope of 'Freedom of speech and expression' given by the constitution.
संविधान द्वारा प्रदत्त 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का तात्पर्य एवं क्षेत्र को समझाइये।
5. Describe the constitutional provisions related to independence of judiciary.
न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
6. Write a note on 'Public Interest Litigation'.
'लोकहित वाद' पर एक लेख लिखिए।
7. Discuss the composition and functions of Election Commission.
चुनाव आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
8. Discuss, with the help of decided cases, the freedom of religion guaranteed by the constitution of India.
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का निर्णीत वादों की सहायता से वर्णन कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग**(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Write the correct answer :

सही उत्तर लिखिए :

1. The constitution of India provides for 'abolition of untouchability' under Article
भारतीय संविधान अनुच्छेद में 'छूआछूत के निषेध' का प्रावधान करता है।
2. The case of A. R. Antulay vs. R. S. Nayak (1988) is related to
ए. आर. अन्तुले बनाम आर. एस. नायक (1988) का वाद से सम्बन्धित है।
3. The duty to provide opportunities for education to his child between the age of 6 and 14 years is a fundamental duty of every citizen under Article of the constitution.
प्रत्येक नागरिक को अपने 6 वर्ष और 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने का मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत उपबन्धित है।

4. Though the Directive Principles of State Policy contained in the constitution are not enforceable by any court, yet they are fundamental in the of the country.

यद्यपि संविधान में अन्तर्विष्ट राज्य नीति निर्देशक तत्त्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी वे देश के में मूलभूत हैं।

5. A corporation is 'State' under Article 12 of the constitution if it is the and of the government.

संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत एक निगम 'राज्य' है, यदि वह सरकार का या है।

6. Article of the constitution imposes a duty on the centre to ensure that the government of the State is carrying on in accordance with the provisions of the constitution.

संविधान का अनुच्छेद केन्द्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चल रही है।

7. The case of *Parmanand Katara vs. Union of India* is related with right against

परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ का वाद के विरुद्ध अधिकार से सम्बन्धित है।

8. 'Triple Talaq' was held unconstitutional by the Supreme Court by a majority of judges.

उच्चतम न्यायालय ने 'तीन तलाक' को न्यायाधीशों के बहुमत से असंवैधानिक कहा।

9. The right of free movement throughout the territory of India under Article 19 can be restricted on the ground of the interest of general public or for the protection of the interests of any

अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने-फिरने में सामान्य लोगों के हित में अथवा के हितों के संरक्षण के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

10. Article 338-A of the constitution provides for the establishment of a

संविधान का अनुच्छेद 338-A की स्थापना के सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

